clear. So would it not be possible for the Government to issue a clear-cut statement saying that in no case will Mr. Phizo be associated with these negotiations?

SHRI B. R. BHAGAT: I think I have clearly stated that it is not possible to have talks with Mr. Phizo as I have explained the reasons.

श्री जे० पी० यादव : श्रीमन्, सरकार के द्वारा विद्रोही नागाओं के साथ आज तक वार्ता करने के कारण देश के और भी पहाड़ी क्षेत्रों में दूसरे पहाड़ी राज्यों की माँग बढ़ी है और इसी संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार कब तक यह निश्चय कर लेगी कि इन विद्रोही नागाओं को या तो वह भारत वर्ष में रहने के लिये बाध्य करेगी या यदि वे भारतवर्ष में रहने के लिये बाध्य नहीं होते हैं वार्तालाप को छोड़कर सरकार उचित कार्यवाही कर के नागालैंड में शांति स्थापित करेगी ।

श्री बी० आर० भगत : मैं यह नहीं मानता कि इस वार्तालाप के कारण दूसरे लोगों में भी यह माँग बढ़ी है । यह बात नहीं है । जहाँ तक नागा लोगों की समस्या का सवाल है, नागालैंड की सरकार वहाँ बनी हुई है, अधिकांश नागा शांति से भारत में रहने में विश्वास करते हैं । यह सब को मालूम है कि इसका हल भारत में रह कर ही हो सकता है, बाहर रह कर नहीं हो सकता है, यह बिलकुल साफ बात है और इसके अतिरिक्त हम और कोई समझौता इस मामले पर करने के लिये तैयार नहीं हैं ।

श्री गोडे मुराहरि : मैं सरकार से यह जानना चाहता हू कि जब पीकिंग एक योजना बना कर नागा, मिजो और इस तरह के विद्रोहियों की सहायता कर रही है और खुले आम उनसे वार्तालाप करके सहयोग दे रही है तो क्या सरकार यह उचित नहीं समझती है कि हम भी तिब्बत के बारे में जो अपनी नीति है उसको बदलें और खुलेआम तिब्बत की जो जनता है, जो उसकी लड़ाई चल रही है चीन के खिलाफ उसमें हम भी अपना सहयोग दें, जितना सक्रिय सहयोग दे सकते हैं दें ?

श्री बी० आर० भगत : जहाँ तक चीन की जो नीति नागा और मिजो के सम्बंध में है उसका सवाल है, हम उसकी पूरी भर्त्सना करते हैं और पूरी शक्ति से कोशिश करेंगे कि उनका गठन बंधन सक्रिय रूप न ले सके, लेकिन इसको तिब्बत के साथ जोड़ना उचित नहीं होगा, वह अलग सवाल है ।

*246. [*The questioner (Shri Y. Adinarayana Reddy) was absent. For answer* vide col. 1902 infra.]

†POSSESSION OF INDIAN LAND BY PAKISTAN

72. SHRI N. R. MUNISWAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Chief Minister of Assam, Shri B. P. Chaliha informed the State Assembly that an area of 748 bighas of land in Lathitilla Dumabari area in Assam is under the illegal possession of East Pakistan; and

(b) if so, what action Government propose to take to restore the land from the illegal possession of Pakistan?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI B. R. BHAGAT): (a) The Chief Minister of Assam had stated in the State Assembly on the 19th March 1968 that according to the prevailing Military Working Boundary Agreement, East Pakistan is in temporary control of about 748 bighas of land in the Lathitilla Dumabari area.

†Transferred from the 1st May, 1968.

(b) The solution to the problem lies in the early joint demarcation of the boundary in this area—and the exchange of adversely held territories. The Government of India have asked the Government of Pakistan to discuss this issue at any level acceptable to Pakistan. Their reply is awaited.

SHRI N. R. MUNISWAMY: Sir, as early as 1958 when the Nehru-Noon Pact was entered into, this question was covered and it has been understood that this forms part of India. Now it has been under illigal occupation of Pakistan for over seven years. I am only afraid that an affidavit may be filed that it has been in adverse possession and we have decided to give this. I would request that a conference should be held with secretary or other officials of the other Government and have this demarcated on the principles of the Redcliffe Award of 1947. I would like to know what steps are proposed to be taken to get it back.

SHRI B. R. BHAGAT: Of course this area belongs to us. There is no doubt about that. There is a proposal to have a meeting of the officers of Assam and East Pakistan and we are trying to persuade Pakistan to settle this question as early as possible.

SHRI N. R. MUNISWAMY: The other question he has not answered; how many families have been affected thereby, whether they have been rehabilitated and whether it is a fact that there is no patrol at all in this area and they have constructed bunkers and dug trenches also.

SHRI B. R. BHAGAT: I want notice for this.

श्री राजनारायण : आसाम के लाठी-टीला-दुमाबाढ़ी क्षेत्र में 748 बीघा हमारी जमीन पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है भारत सरकार को इसकी जानकारी कब हुई ?

श्री बी० आर० भगत : यह तो पुराना मामला चल रहा है ।

Even the 1959 Swaran Singh-Sheikh Agreement provided for some temporary arrangements

श्री राजनारायण : सुनाई नहीं पड़ता, ठीक से बोलिये ।

श्री बी० आर० भगत : एग्जक्ट डेट बताना मुश्किल है । जैसा मैंने कहा 1959 में स्वर्ण सिंह जी और शेख एग्रीमेंट हुआ था उसमें भी ऐसी बातों के हल करने का जिक्र है और उसके बाद हर बार इसका जिक्र आया है ।

श्री राजनारायण : तो जब 1959 में इस सरकार को जानकारी हो गई कि 748 बीघे हमारी जमीन पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है तो इस जमीन को लेने के लिये अब तक सरकार ने—9 साल व्यतीत हो गए—क्या कार्यवाही की ?

श्री बी० आर० भगत : जनवरी 1962 तक आसाम गवर्नमेंट का इस सब इलाके पर कब्जा था । उसके बाद झगड़े हुए, टेंशन हुआ, कई बार गोलियाँ चलीं उसके बाद पाकिस्तान ने 4-5 गाँवों पर कब्जा कर लिया था । उसके बाद के एग्रीमेंट में यह बात आई । अभी बेरूबाड़ी को लेकर जो बंगाल की सीमा पर है पाकिस्तान का यह रुख रहा है कि जब तक बेरुबाड़ी का सवाल तय नहीं हो जाता जब तक हम इन बातों को नहीं उठायेंगे । खैर डिमारकेशन हो रहा है । मैंने कहा बेरुबाड़ी का सवाल कोर्ट की वजह से रुका हुआ है कोई हमारी नीयत का सवाल नहीं है ये सब मामले तय हो जायं बेरूबाड़ी का भी तय हो ही जायगा ।

(Interruptions)

SHRI RAJNARAIN: Sir, on a point of information.

श्री पीताम्बर दास : यह भी तो बताइए कि इसका उन्होंने क्या जवाब दिया ।

SHRI RAJNARAIN: Sir, on a point of information.

MR. CHAIRMAN: What is the point of information you want?

श्री राजनारायण : मंत्री जी ने पहले कहा कि 1959 में स्वर्ण सिंह जी की बातचीत में इसकी चर्चा हुई थी । अभी यह कह रहे हैं कि 1962 तक यह जमीन आसाम राज्य के कब्जे में थी । इन दोनों में कौन सा उत्तर सही है ।

श्री बी० आर० भगत : जहाँ तक कब्जे का सवाल है मैंने कहा 1962 तक कब्जा था । 1959 में इसके बारे में बातचीत हुई थी ।

श्री राजनारायण : श्रीमन् हमारी सुरक्षा करें । मैंने यह साफ पूछा कि सरकार को कब जानकारी हुई कि यह जमीन पाकिस्तान के कब्जे में है । तो इन्होंने कहा उसके उत्तर में कि 1959 से । अब दूसरे उत्तर में कहते हैं कि 1962 तक यह आसाम के कब्जे में था । इन दोनों उत्तरों में साम्यता नहीं है दो में दो उत्तर हैं । मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या यह भारत की सरकार भारत की सीमा के साथ हमेशा खिलवाड़ करती रहेगी ? अभी भी मंत्री जी जिस सामान्य तरीके से जवाब दे रहे है उससे मालूम होता है जैसे कुछ हुआ ही नही है । हमारी मातृभूमि कटती जा रही है हमारी जमीन पर विदेशी कब्जा होता जा रहा है । देश की जमीन, देश की सीमा का सम्बन्ध शरीर की त्वचा जैसा है । अगर त्वचा के किसी हिस्से में सुई चुभने से जैसे शरीर सिहर उठता है उसी तरह से जो सरकार अपनी सीमा को त्वचा की तरह समझेगी वहीं सरकार देशभक्त हो सकती है । तो अगर मैं सरकार के ऊपर दोषारोपण करूं कि यह सरकार देश के साथ गद्दारी कर रही है तो क्या यह हमारा अपराध होगा, मैं यह पूछता चाहता हूं ?

श्री सी० डी० पांडे : अपराध ही है ।

श्री बी० आर० भगत : जहाँ तक इन पाँच गाँवों का सवाल है गद्दारी का सवाल नही है ये निश्चित रूप से हमारे है, पाकिस्तान ने उन पर ग़लत कब्जा किया है और इस बारे में कोई दो रायें नहीं हैं इन गाँवों पर हमारा क्लेम है । हम चाहते है कि उनसे बातचीत करके मामला तय हो जाय । जहाँ तक इन गाँवों का सवाल है वे तो हमारे हैं ही ।

श्री राजनारायण : कच्छ एग्रीमेंट के समय यह सवाल क्यों नही उठा कि हमारे उधर भी गाँव हैं । *(Interruptions)*

No reply.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से एक निवेदन करना चाहता हूं । इसी राज्यसभा में तारांकित प्रश्न संख्या 110, दिनाँक 2-5-68 को जवाब देते समय मुझे यह कहा गया कि लाठीटीला दुमाबाड़ी गाँव के 18 परिवार 1962 से पाकिस्तान के कब्जे के कारण अपनी भूमि अस्थायी रूप से खो बैठे है । तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि इन परिवारों के बारे में, जिनके कब्जे की भूमि चली गई, 1962 से लेकर आज 1968 तक क्या कदम उठाया गया है उनको बसाने की क्या व्यवस्था की गई है और उनकी जमीन फिर से उन्हें प्राप्त हो इसके लिये क्या इन्तजाम किया गया ।

श्री बी० आर० भगत : जब पाकिस्तान ने नाजायज ढंग से कब्जा कर लिया तो ये परिवार वहाँ से चले आए ।

श्री राजनारायण : कहाँ चले आए, कहाँ है, हिन्दुस्तान के किस हिस्से में हैं ?

श्री बी० आर० भगत किस गाँव में है, कहाँ हैं, यह मेरे पास सूचना नही है ।

श्री राजनारायण : इन्हें जीवन निर्वाह का साधन देने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या किया ?

श्री बी० आर० भगत : ये कहां है, क्या कर रहे है इसके बारे में तफसील से प्रश्न आए तो सूचना दी जा सकती है । अब सवाल उनको वापस लाने का है । वह जुड़ा हुआ है उस जमीन से जो पाकिस्तान के कब्जे में है । इसमें कोई दो राय नहीं है कि वह जमीन हमारी है जब वह मुक्त होकर, डिमारकेशन होकर हमारे पास आएगी तब ये सारे मामले हल होंगे ।

MR. CHAIRMAN: The question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ACTION AGAINST NEWSPAPER PRECHING COMMUNALISM

*244. SHRI ABID ALI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state the action taken by Government against newspapers, journals which preach communalism and other unsocial activities and how many of these have been black-listed for Government advertisements and other facilities?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. K. SHAH): Government advertisements are withheld from such newspapers and periodicals as fall below the accepted journalistic standards or indulge in virulent propaganda inciting communal passions, or preach violence, or offend socially accepted conventions of public decency and morals, thus undermining the basic national interests. Sixteen newspapers are not being used by the Directorate of Advertising and Visual Publicity for Central Government advertisements in keeping with the above principles. No action has been taken to deny normal facilities provided by the Press Information Bureau to such papers.

WEST GERMAN'S CHEQUE TO A CITIZEN OF J. & K.

*246. SHRI Y. ADINARAYANA REDDY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a report published in a Journal "Enlite" of the 9th March, 1968 about a cheque sent to a citizen of Jammu and Kashmir by a West German addressing it as "Jammu and Kashmir, Pakistan"; and

(b) if so, what is our embassy doing in West Germany to educate the West Germans about the location of Jammu and Kashmir in India and not in Pakistan?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI B. R. BHAGAT): (a) and (b) Yes, Sir. Our Embassy took up the matter with the management of the bank concerned and the management have apologised saying that it was a clerical error. Our Embassy in West Germany, as our Embassies elsewhere, make constant efforts to explain that Jammu and Kashmir is part of India.

EXCHANGE OF ENCLAVES BETWEEN INDIA AND PAKISTAN

247. SHRI S. S. MARISWAMY:
SARDAR RAM SINGH:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Prime Minister recently stated while talking to a delegation from the Indian enclaves in East Pakistan that the Government of India would favour an exchange of enclaves between the two countries without delay?

(b) if so, what are the details of the said statement;

(c) what is the reaction of the Government of Pakistan in this regard;

(d) what is the number of Indian enclaves in East Pakistan and details